

मुकदमों का विवरण

कोंकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.

चीनब्रिज परियोजना (2023 की सिविल अपील संख्या 2903)

अगस्त 17, 2023

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, सीजेआई, पामिदिगंतम श्री नरसिम्हा और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: तत्काल अपील में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा एक अपील यू/एस में पारित आदेश की वैधता। 37 माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 जिसके द्वारा माध्यस्थता न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समवर्ती निर्णय यू/एस। 34 सभी दावों को खारिज करने वाले अधिनियम को चुनौती दी जाती है और कुछ दावों की अनुमति दी जाती है।

माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 34 और 37-माध्यस्थ अधिनिर्णय-माध्यस्थ न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा विवादों से संबंधित संविदात्मक खंड की समवर्ती व्याख्या। 34 - एक अपील यू/एस में डिवीजन बेंच द्वारा हस्तक्षेप। 37 - न्यायसंगत उद्धरण:

आयोजित किया गया: उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अपनाए गए अनुबंधों की व्याख्या का सिद्धांत कि जब दो निर्माण संभव हैं, तो अदालतों को उस निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए जो सभी खंडों को प्रभावी और आवाज देता है, जिसका पूर्ण अनुप्रयोग नहीं है-उक्त व्याख्या उस अधिकार क्षेत्र के अधीन है जिसका प्रयोग करने के लिए एक अदालत को कहा जाता है-यू/एस के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय। 37, न्यायालय उस अधिकारिता के बारे में चिंतित है जो एस। 34 न्यायालय ने माध्यस्थ पुरस्कार-क्षेत्राधिकार यू/एस की चुनौती पर विचार करते हुए प्रयोग किया। 34 इसका प्रयोग केवल यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या माध्यस्थ न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण विकृत है या स्पष्ट रूप से मनमाना है-एक वैकल्पिक दृष्टिकोण पर अनुबंध की पुनर्व्याख्या उत्पन्न नहीं होती है-यू/एस के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाली खंड पीठ। 37 एकल न्यायाधीश के निर्णय से बहुत कम-तथ्यों पर, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यू/एस के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक संविदात्मक खंड की पुनः व्याख्या करने में गलती की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

और मध्यस्थता न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समवर्ती निर्णयों को दरकिनार करते हुए-मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय को यू/एस।34 इसे विकृत या स्पष्ट रूप से अवैध नहीं कहा जा सकता है-मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है, और एकल न्यायाधीश इसमें हस्तक्षेप करने से बचते हैं।34 - डिवीजन बेंच को इन आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था-इस प्रकार, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और एकल न्यायाधीश के फैसले को बहाल कर दिया जाता है।[पैरा 20,22,24 और 25]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996।34 और 37-निम्नलिखित के अंतर्गत अधिकारिता का क्षेत्र:**

आयोजित किया गया:न्यायालय का क्षेत्राधिकार यू/एस।37 न्यायालय यू/एस के अधिकार क्षेत्र के समान है।34 - अपील यू/एस में अदालत द्वारा हस्तक्षेप का दायरा।37, किसी आदेश की जांच करने में, किसी पुरस्कार को अलग रखने या अलग रखने से इनकार करना, प्रतिबंधित है और चुनौती यू/एस के समान आधारों के अधीन है।34 - इस प्रकार, यू/एस के तहत अधिकार क्षेत्र का दायरा।34 और एस।37 सामान्य अपीलीय अधिकारिता के समान नहीं है-न्यायालयों को आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए-केवल तथ्यों पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण या अनुबंध की व्याख्या की संभावना अदालतों को मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निर्णयों को उलटने का अधिकार नहीं देती है।[पैरा 14 और 15]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

राधा सुंदर दत्ता बनाम मोहम्मद जहादुर रहीम और अन्य ए. आई. आर 1959 एस. सी. 24:[1959] एससीआर 1309; यूएचएल पावर कंपनी लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2022) 4 एससीसी 116; साउथ ईस्ट एशिया मरीन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड बनाम ऑयल इंडिया लिमिटेड (2020)

5 एससीसी 164:[2020] 4 एस. सी. आर. 254; अडानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड बनाम गुजरात विद्युत नियामक आयोग और अन्य। (2019) 19 एस. सी. सी. 9; सत्यनारायण कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम भारत संघ और अन्य। (2011) 15 एस. सी. सी 101; दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम आर. एस. शर्मा और

कंपनी, नई दिल्ली (2008) 13 एससीसी 80:[2008] 12 एससीआर 785; एम. एम. टी. सी. लिमिटेड बनाम.वेदांत लिमिटेड (2019) 4 एस. सी. सी. 163:[2019] 3 एस. सी. आर. 1023; यू. एच. एल. पावर

कंपनी लिमिटेड बनाम.हिमाचल प्रदेश राज्य (2022) 2 एससीसी (सिविल) 401; डायना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम क्रॉम्पटन ग्रीन्स लिमिटेड (2019) 20 एससीसी 1; सांगयोंग इंजीनियरिंग& कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनामभारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) (2019) 15 एससीसी 131:[2019] 7 एस. सी. आर. 522; पारसा कंटे कोलियरीज लिमिटेड बनाम.राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन

निगम लिमिटेड (2019) 7 एस. सी. सी. 236:[2019] 8 एससीआर 728; पटेल इंजीनियरिंग 217

कोंकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम चीनब्रिज परियोजना

लिमिटेड बनाम नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2020) 7 एस. सी. सी. 167:[2020] 4 एससीआर 156; विद्या द्रोलिया और ओआरएस. वी.दुर्गा व्यापार

निगम (2021) 2 एससीसी 1:[2020] 11 एससीआर 1001; एसोसिएट बिल्डर्स बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (2015) 3 एससीसी 49:[2014] 13 एस. सी. आर. 895-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपील न्यायनिर्णय:सिविल अपील No.2903

2023.

2019 के ए. एन. No.458 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 23.09.2022 से।

रूप:

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, अमलान कुमार, सुश्री मुशर्रफ शेख, सुश्री रुक्मिणी बोबडे, सुश्री सौम्या प्रियदर्शिनी, अंकित अम्बास्ता, अमित कुमार श्रीवास्तव, विशाल प्रसाद, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

डेरियस खंबाटा, वरिष्ठ अधिवक्ता, अवीक गांगुली, मनु शेषाद्री, सुश्री पल्लवी आनंद, अभिजीत लाल, मिथु जैन, सुश्री सौम्या, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.

1. यह अपील मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 37 के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय से उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा सभी दावों को खारिज करने वाले अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के एकल

न्यायाधीश के समवर्ती निर्णय को खारिज कर दिया गया था और कुछ दावों की अनुमति दी गई थी। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की यह अपील अधिनियम की धारा 37 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश की वैधता को चुनौती देती है।

2. इस अपील के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं: के. एम. 50/800 पर एक पुल के निर्माण के लिए प्रतिवादी की निविदा

1 इसके बाद 'अधिनियम' बना।

218

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक के कटरा-लाओले खंड, जिसे दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे पुल कहा जाता है, को अपीलार्थी द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिससे 24.11.2004 पर अनुबंध का निष्पादन किया गया।

3. जब अनुबंध निष्पादन में था, पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए और एक समझौते के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए एक स्थायी मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया। प्रत्यर्थी ने 35 दावे किए जिन्हें बारह विवादों के रूप में वर्गीकृत और वर्गीकृत किया गया था। वर्तमान कार्यवाहियाँ मध्यस्थ न्यायाधिकरण के तीन विवादों का निर्णय लेने के निर्णय से उत्पन्न होती हैं, जिनमें विवाद I (दावा 9 से संबंधित), विवाद III (दावा 12, 22 और 28 से संबंधित) और विवाद IV (दावा 13, 23 और 29 से संबंधित) शामिल हैं।

4. मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 15.11.2014 के निर्णय द्वारा तीनों विवादों पर विचार किया और सभी दावों को खारिज कर दिया। प्रत्यर्थी ने अधिनियम की धारा 34 के तहत पुरस्कार को चुनौती दी। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पुरस्कार स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती को खारिज करने के लिए आगे बढ़े। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय को प्रत्यर्थी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील की गई थी, और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इसमें आक्षेपित आदेश द्वारा आंशिक रूप से निम्नलिखित तरीके से अपील की अनुमति दी थी। डिवीजन बेंच ने विवाद I के संबंध में अपील को खारिज करते हुए, शेष दो विवादों (विवाद III और IV) के संबंध में अपील को मंजूरी दी, और इस तरह इन विवादों के संबंध में समवर्ती निर्णयों को दरकिनार कर दिया। चूंकि विवाद I के संबंध में कोई विवाद नहीं है, इसलिए हमें विवाद III और IV के संबंध में आदेश की वैधता की जांच करने के लिए कहा जाता है।

5. विवाद III के लिए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं: प्रत्यर्थी के पक्ष में अनुबंध 24.11.2004 पर किया गया था। उस समय जम्मू और कश्मीर सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.12.2003 ने पृथ्वी पर चलने वाले उपकरणों पर प्रवेश कर से छूट दी थी। हालाँकि,

अनुबंध के निष्पादन के दौरान, 25.01.2008 पर, जम्मू और कश्मीर सरकार ने छूट अधिसूचना वापस ले ली। नतीजतन, प्रत्यर्थी ने रुपये की प्रतिपूर्ति के लिए दावे किए। 1,32,29,771/- प्रवेश कर के भुगतान के कारण किया गया।

6. जहाँ तक विवाद IV का संबंध है, यह मशीनरी और सामग्रियों पर टोल कर की प्रतिपूर्ति से संबंधित है। जम्मू और कश्मीर में मौजूदा नीति के अनुसार, निविदा जमा करने की तारीख को लागू टोल टैक्स, जो कि 31.05.2004 है, रु। 400/- प्रति मीट्रिक टन। हालांकि, जम्मू और कश्मीर टोल टैक्स अधिनियम, 1998 के तहत जारी चार बाद की अधिसूचनाओं के माध्यम से, 219

कोंकण रेल कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम चिनाब ब्रिज परियोजना का प्रबंधन [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.]

करों को उत्तरोत्तर बढ़ाकर रु। 650/- प्रति मीट्रिक टन। नतीजतन, प्रत्यर्थी ने रुपये का दावा किया। 5,23,279/-, अनुबंध के निर्वाह के दौरान टोल कर में वृद्धि के कारण हुआ।

7. विवाद III के साथ-साथ विवाद IV के तहत दावों पर अनुबंध के प्रासंगिक खंडों के संदर्भ में विचार किया जाना था, जो खंड 5.1 हैं। 2, 7.1.1, 7.1.2, और 11.7। इन खंडों को तैयार संदर्भ के लिए नीचे निकाला गया है। अध्याय 5 के खंड 5 का प्रासंगिक भाग, जिसका शीर्षक 'बिक्री कर, परिवर्तन कर/स्थानीय कर, शुल्क आदि' है, निम्नानुसार है:

“खंड 5.1 बिक्री कर/परिवर्तन कर/स्थानीय कर, शुल्क आदि।

.....

खंड 5.1।2 निविदा शुरू होने की तारीख से 15 दिन पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा लागू कार्य अनुबंध, चुंगी, रॉयल्टी, टोल कर, शुल्क/शुल्क के साथ-साथ सेवाओं और किसी भी अन्य कर पर टर्न ओवर कर सहित बिक्री कर को वस्तुओं, दरों और मात्राओं की अनुसूची में निविदाकारों द्वारा उद्धृत प्रतिशत दरों में शामिल माना जाएगा। निविदा खोलने की तारीख से 15 दिन पहले से काम पूरा होने तक की अवधि के दौरान करों में किसी भी वृद्धि/कमी के मामले में, काम के शेष हिस्से के लिए शुद्ध वृद्धि/कमी निगम द्वारा वहन/वसूल की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर राज्यों में स्रोत पर काटे जाने वाले कार्य अनुबंध कर (डब्ल्यू. सी. टी.) की प्रचलित दर राज्य कर विभाग के साथ पंजीकृत उन लोगों के लिए 4.2 प्रतिशत है जिनके पास पंजीकरण नहीं है, यह दर 8.2 प्रतिशत है।

खंड 5.1।3 निगम समय-समय पर संबंधित निकायों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार लागू दर पर ठेकेदार के बिल से बिक्री कर/चालू कर या किसी अन्य कर की कटौती करेगा और इसे संबंधित विभाग को भेजेगा और ठेकेदार द्वारा मांग पर इस तरह काटे गए कर/शुल्क के बारे में

एक प्रमाण पत्र जारी करेगा।” 7.1.खंड 7.1।1 7. 1.2 अध्याय 7 से, 'मूल्य परिवर्तन' शीर्षक से, निम्नानुसार हैं:

“खंड **7.1।1** निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत और निगम द्वारा स्वीकार की गई दरें कार्य के पूरा होने तक और **220** सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट **[2023] 11 एस. सी. आर.** तक अच्छी होंगी।

बाजार दरों में वृद्धि, करों में वृद्धि/किसी अन्य शुल्क/शुल्क आदि के कारण कोई अतिरिक्त व्यक्तिगत दावा स्वीकार्य नहीं होगा, सिवाय इसके कि समग्र बाजार स्थिति के लिए भुगतान/वसूली नीचे दिए गए मूल्य भिन्नता खंड के अनुसार की जाएगी।

खंड 7.1।2 भुगतान में समायोजन करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्तिगत वस्तु के लिए करों और अन्य बाजार स्थितियों आदि में किसी भी प्रकार के उतार-चढ़ाव के लिए कोई संज्ञान नहीं दिया जाएगा।हालाँकि, अनुबंध नीचे दिए गए सामान्य मूल्य भिन्नता खंड द्वारा शासित होगा।”

7.2.खंड 11.7, अध्याय 11 में, जिसका शीर्षक 'वस्तुओं, दरों और मात्राओं की अनुसूची-मात्राओं का बिल' है, निम्नानुसार है:

“खंड 11.7 मात्राओं के मूल्य निर्धारण बिल में दी गई दरों और कीमतों में, जहां तक अनुबंध के तहत अन्यथा प्रावधान किया गया है, सभी निर्माण संयंत्र, श्रम, पर्यवेक्षण, सामग्री, सभी अस्थायी कार्य, झूठे काम, सभी लीड और लिफ्ट, निर्माण, विनिर्दिष्ट शुल्क, रखरखाव, स्थापना और ओवरहेड शुल्क, बीमा, लाभ, विदेशी कराधान और शुल्क, कर, रॉयल्टी और शुल्क के साथ-साथ अनुबंध में निर्धारित या निहित सभी सामान्य जोखिम, देनदारियों और दायित्वों और दोष देयता अवधि के दौरान किसी भी दोष का उपचार शामिल होगा।”

8. मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय:मध्यस्थ न्यायाधिकरण

अनुबंध की व्याख्या की और खंड 5.1 का अर्थ लगाया।2 उन करों के विपरीत जो 'दरों की वस्तुओं की अनुसूची-मात्रा के बिल' में उद्धृत सामग्री का हिस्सा थे, प्रत्यर्थी-ठेकेदार द्वारा सीधे अपीलार्थी पर लगाए जा सकने वाले करों तक सीमित अनुबंध का।इसके लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अनुबंध के खंड 11.7 पर भी भरोसा किया।मध्यस्थ न्यायाधिकरण का विचार था कि पृथ्वी पर चलने वाले उपकरणों पर प्रवेश कर राशि के बिल में उद्धृत कार्यों की लागत का हिस्सा है।इस कारण से, मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि खंड 5.1 के तहत प्रवेश कर लगाने के कारण बढ़े हुए दायित्व की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। 2, क्योंकि इसके लिए प्रतिपूर्ति केवल मूल्य परिवर्तन खंडों (अध्याय 7 में खंड 7.1.1 और 7.1.2) द्वारा नियंत्रित की जा सकती है।

8.1 मूल्य परिवर्तन खंडों की व्याख्या करते हुए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने नोट किया कि अनुबंध केवल 221 के आधार पर सामान्य मूल्य भिन्नता के लिए प्रदान किया गया है।

मानकीकृत सूत्र।इसने यह भी पाया कि खंड 7.1।2 विशिष्ट कैली वर्जित

"भुगतान में समायोजन करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्तिगत वस्तु के लिए करों में किसी भी प्रकार की वृद्धि और अन्य बाजार स्थितियों" का संज्ञान।

तदनुसार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि व्यक्तिगत या विशिष्ट वस्तुओं के लिए बड़े हुए कर दायित्व की भरपाई के दावे, इस मामले में, प्रवेश कर के अधिरोपण की प्रतिपूर्ति खंड 7.1 के तहत नहीं की जा सकती है।¹ 7. 1.2.

8.2 न्यायाधिकरण ने तर्क दिया कि ठेकेदार को उस समय इन शर्तों के बारे में पता था जब कीमतें उद्धृत की गई थीं, और इसलिए, मूल्य परिवर्तन खंडों के तहत दावा सफल नहीं हो सका।

8.3 जहां तक टोल कर के दावे के संबंध में, जो विवाद IV का हिस्सा था, न्यायाधिकरण ने संविदात्मक खंडों की समान व्याख्या को अपनाया और दावे को खारिज कर दिया।

9. अधिनियम की धारा 34 के तहत उच्च न्यायालय का निर्णय:द.

अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थ पुरस्कार के लिए प्रत्यर्थी की चुनौती पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अपने दिनांक 17.01.2019 के आदेश द्वारा विचार किया गया और खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अनुबंध के प्रासंगिक खंडों के निर्माण के संबंध में दो संभावित विचार थे। हालाँकि, जैसा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एक व्याख्या को अपनाया और चूंकि यह एक उचित व्याख्या थी, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने माना कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए अधिनियम की धारा 34 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए कोई औचित्य नहीं था।

10. अधिनियम की धारा 37 के तहत खंड पीठ का निर्णय:द.

उच्च न्यायालय की खंड पीठ, अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील पर विचार करते हुए, संविदात्मक खंडों की पुनः व्याख्या करने के लिए आगे बढ़ी और एक विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंची। डिवीजन बेंच ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण और एकल न्यायाधीश की खंड 5.1 की व्याख्या को खारिज कर दिया।² और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उक्त खंड में अप्रत्यक्ष कर जैसे सेवा कर, जी. एस. टी., कार्य अनुबंध कर आदि भी शामिल होंगे। ऐसा करते समय, डिवीजन बेंच ने खंड 5.1 में प्रवेश कर को भी शामिल करने के लिए सामान्य न्याय के सिद्धांत को लागू किया।² उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष को इस आधार पर उलट दिया कि उन्होंने केवल यह मान लिया था कि

मात्रा के बिल का हिस्सा बनने वाली वस्तुओं की कर देयता उद्धृत लागत में 'अंतर्निहित' थी और इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था। डिवीजन बेंच ने यह भी नोट किया कि वृद्धि के कारण प्रतिपूर्ति

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

'टोल कर' में खंड 5.1 में विशिष्ट रूप से प्रावधान किया गया था। 2 अनुबंध का, और इसलिए, उसी के दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, खंड पीठ ने खंड 7.1 का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा। 1 और 7.1.2 मूल्य भिन्नता खंडों से संबंधित, क्योंकि दावों को न्यायसंगत ठहराया गया था

खंड 5.1। 2 स्वयं। अंत में, राधा सुंदर दत्ता बनाम मोहम्मद जहादुर पर भरोसा करना।

रहीम और अन्य, 2 उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह एक "अच्छी तरह से व्यवस्थित" है।

सिद्धांत यह है कि यदि किसी अनुबंध के दो निर्माण संभव हैं, तो जो सभी खंडों को प्रभाव और आवाज देता है, उसे दूसरे पर प्राथमिकता दी जाएगी जो उनमें से एक को विषम या निरर्थक बनाता है। इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए,

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण संविदात्मक खंडों की सामंजस्यपूर्ण और समग्र रूप से व्याख्या करने में विफल रहा। इसने अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण विकृति के बराबर होगा, और इसलिए, पुरस्कार को दरकिनार करना और विवाद III और IV के तहत आने वाले दावों की अनुमति देना आवश्यक पाया।

11. उच्च न्यायालय की खंड पीठ के इस फैसले के कारण हमारे समक्ष वर्तमान दीवानी अपील दायर की गई।

12. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ: श्री श्याम दीवान, वरिष्ठ

अपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणचअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणओअपीलार्थीगणअपीलार्थीगणअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगणअपीलार्थीगणओअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणअपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगणअपीलार्थीगणशअपीलार्थीगणअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगणअपीलार्थीगणअअपीलार्थीगणमअपीलार्थीगणलअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणुअपीलार्थीगणमअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण,अपीलार्थीगणअपीलार्थीगणशअपीलार्थीगणअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगण

अपीलार्थीगणउअपीलार्थीगणपअपीलार्थीगणसअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणथअपीलार्थीगणिअपी

लार्थीगणतअपीलार्थीगण अपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणुअपीलार्थीगणएअपीलार्थीगण।
अपीलार्थीगणउन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अनुबंध की पुनः व्याख्या करके और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए अपने विचार को प्रतिस्थापित करके अधिनियम की धारा 37 के तहत अपने सीमित अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया, अपील न्यायालय की भूमिका ग्रहण की।वे यूएचएल पावर कंपनी लिमिटेड पर निर्भर थे।

इस उद्देश्य के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य 3 और दक्षिण पूर्व एशिया मरीन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड बनाम ऑयल इंडिया लिमिटेड 4।

12.1 इसके बाद, उन्होंने प्रस्तुत किया कि पक्षकार प्रत्यर्थी-ठेकेदार को देय एकमुश्त अनुबंध मूल्य पर सहमत हुए। ठेकेदार सहमत कीमतों को कई घटकों में विभाजित करता है और 'वस्तुओं और दरों की अनुसूची-मात्रा के बिल' में विभाजन का संकेत देता है, जिससे उसमें उल्लिखित वस्तुओं के निष्पादन में शामिल लागत और प्रभाव उत्पन्न होता है। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि प्रविष्टियों के निष्पादन में खर्च की गई राशि की अलग से प्रतिपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि अनुबंध का खंड 11.7 स्पष्ट रूप से इंगित करता है

2 ए. आई. आर 1959 एस. सी. 24. 3 (2022) 4 एससीसी 116। 4 (2020) 5 एससीसी 164।

223

कोंकण रेलवे कॉर्पो. लिमिटेड बनाम चीनब ब्रिज प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग [पामिदिगंतम श्री नरसिम्हा, जे.]
224 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

कि राशि के बिल में उल्लिखित कीमतों में उन सभी लागतों को शामिल किया गया है जो अनुबंध के निष्पादन में होने वाली हैं।

12.2 इसके अलावा, उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने खंड 5.1 की समग्र रूप से व्याख्या की। 2, 7.1.1 7. 1.2 यह राय देने के लिए अनुबंध की कि व्यक्तिगत कर दावों की प्रतिपूर्ति अपीलार्थी-निगम द्वारा नहीं की जाएगी। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि खंड 5.1। 2 यह एक अलग क्षेत्र में काम करता है, यानी यह निगम द्वारा ठेकेदार को सीधे देय करों के क्षेत्र में काम करता है। उन्होंने आगे कहा कि खंड 5.1 में टोल कर और चुंगी का उल्लेख किया गया है। 2 यह केवल आकस्मिक है और ठेकेदार द्वारा करों की वसूली को निहित नहीं करता है। दूसरी ओर, मात्रा के बिल (या निर्माण सामग्री और मशीनरी को जुटाने के लिए) में प्रविष्टियों की कीमत में वृद्धि केवल खंड 7.1 में मूल्य परिवर्तन की योजना के अनुसार ही वसूली योग्य थी। 1 7. 1.2, जो स्पष्ट रूप से अलग-अलग वस्तुओं की कीमत में वृद्धि का संज्ञान नहीं लेते हैं।

13. उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ: श्री डेरियस खंबाटा,

ठेकेदार-प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अवीक गांगुली, श्री मनु शेषाद्री, सुश्री पल्लवी आनंद, श्री अभिजीत लाल, सुश्री सौम्या, अधिवक्ता और श्री मिट्ठू जैन, एओआर उपस्थित हुए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के कार्यों में

उचित रूप से हस्तक्षेप किया क्योंकि उसने अनुबंध को फिर से लिखा था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि संविदात्मक व्याख्या का प्रत्येक सिद्धांत विरोधाभासी प्रतीत होने वाले खंडों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण और अनुबंधों के निर्माण का प्रावधान करता है ताकि किसी भी खंड को अनुचित न माना जाए। 13.1 उन्होंने प्रस्तुत किया कि निस्संदेह, खंड 5.1।2 7. 1.1 अलग-अलग अधिनियमों में कार्य करना, अर्थात् खंड 5.1।2 अनुबंध की विशेष शर्तों का एक विशेष खंड है जो करों से संबंधित है और निगम द्वारा करों में वृद्धि के कारण प्रतिपूर्ति का प्रावधान करता है। खंड 7.1।1 7. 1.2, दूसरी ओर, खंड 5.1 में पहले से उल्लिखित दावों के अलावा, मूल्य भिन्नता के लिए अतिरिक्त और व्यक्तिगत दावों को प्रतिबंधित करें। 2. खंड 5.1 को सीमित करके। 2 निगम पर ठेकेदार द्वारा बिल किए जा सकने वाले करों के लिए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अनुबंध की शर्तों को अनिवार्य रूप से फिर से लिखा। अनुबंध के प्रावधानों को सुसंगत बनाने के बजाय, इसने इसमें नई शर्तें और विरोधाभास जोड़े।

13.2 प्रत्यर्थांगण ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ अधिनियम की धारा 37 के तहत आंशिक रूप से पुरस्कार को रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में थी। अपनी दलीलों को साबित करने के लिए, वे

अडानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड बनाम गुजरात विद्युत नियामक आयोग और अन्य, 5 राधा सुंदर दत्ता बनाम मोहम्मद जहादुर रहीम और अन्य (ऊपर), सत्यनारायण कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम भारत संघ और अन्य, 6 और दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम आर. एस. शर्मा और कंपनी, नई दिल्ली। 7

14. विश्लेषण: शुरुआत में, हम यह बता सकते हैं कि अधिनियम की धारा 37 के तहत न्यायालय की अधिकारिता, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा एम. एम. टी. सी. लिमिटेड बनाम वेदांता लिमिटेड, अधिनियम की धारा 34 के तहत अदालत के अधिकार क्षेत्र के समान है। 8 अधिनियम की धारा 37 के तहत एक अपील में एक अदालत द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश, एक आदेश की जांच करने में, एक पुरस्कार को अलग करने या अलग करने से इनकार करने में, प्रतिबंधित है और अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती के समान आधारों के अधीन है।

15. इसलिए, अधिनियम की धारा 34 और धारा 37 के तहत अधिकार क्षेत्र का दायरा सामान्य अपीलीय अधिकार क्षेत्र के समान नहीं है। 9 यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अदालतों को आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तथ्यों या अनुबंध की व्याख्या पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की केवल संभावना अदालतों को अनुबंध को उलटने का अधिकार नहीं देती है।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय। 10 डायना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में

बनाम क्रॉम्पटन ग्रीन्स लिमिटेड (2019) 20 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

“24. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 किसी निर्णय को चुनौती देने को केवल उसमें दिए गए आधारों या विभिन्न न्यायालयों द्वारा व्याख्या के आधार पर सीमित करती है। हमें इस तथ्य से अवगत होने की आवश्यकता है कि मध्यस्थता पुरस्कारों में आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि

5 (2019) 19 एस. सी. सी. 9.

6 (2011) 15 एससीसी 101।

7 (2008) 13 एससीसी 80।

8 (2019) 4 एससीसी 163: “पैरा 14. जहां तक धारा 37 के अनुसार धारा 34 के तहत किए गए आदेश में हस्तक्षेप का संबंध है, यह विवादित नहीं हो सकता है कि धारा 37 के तहत इस तरह का हस्तक्षेप धारा 34 के तहत निर्धारित प्रतिबंधों से परे नहीं जा सकता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय पुरस्कार के गुण-दोष का स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कर सकता है, और उसे केवल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 34 के तहत न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग प्रावधान के दायरे से अधिक नहीं है।”

9 यू. एच. एल. पावर कंपनी लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2022) 2 एस. सी. सी. (सी. वी.) 401, पैरा 15। यह भी देखें: डायना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड (2019) 20 एस. सी. सी. 1, पैरा 24, 25.

10 आई. बी. आई. डी.; सांगयोंग इंजीनियरिंग & कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन. एच. ए. आई.) (2019) 15 एस. सी. सी. 131; पारसा कंटे कोलियरीज लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, (2019) 7 एस. सी. सी. 236, पैरा 11.

225

कोंकण रेलवे कॉर्पो. लिमिटेड बनाम चीनब ब्रिज प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग [पामिदिगंतम श्री नरसिम्हा, जे.]

226 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

पंचाट की विकृति मामले की जड़ तक जाती है, बिना वैकल्पिक व्याख्या की संभावना के जो मध्यस्थ पंचाट को बनाए रख सकती है। धारा 34 अपने दृष्टिकोण में अलग है और इसे सामान्य अपीलिय क्षेत्राधिकार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। धारा 34 के तहत अधिदेश मध्यस्थता पुरस्कार की वास्तविकता और कानून के तहत प्रदान किए गए एक वैकल्पिक मंच द्वारा अपने विवाद का निर्णय लेने के लिए पार्टी की स्वायत्तता का सम्मान करना है। यदि अदालतें तथ्यात्मक पहलुओं पर सामान्य पाठ्यक्रम में मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप करती हैं, तो वैकल्पिक विवाद समाधान का विकल्प चुनने के पीछे वाणिज्यिक ज्ञान निराश हो जाएगा।

25. इसके अलावा, इस न्यायालय के कई निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अदालतों को केवल तथ्यों और अनुबंध की व्याख्या पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण मौजूद होने के कारण किसी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अदालतों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को टालना चाहिए, भले ही निर्णय में प्रदान किया गया तर्क निहित हो, जब तक कि ऐसा निर्णय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अक्षम्य विकृति को चित्रित नहीं करता है।

16. वर्तमान मामले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने संविदात्मक खंडों की व्याख्या की और विवाद I, III और IV से संबंधित प्रत्यर्थी के दावों को खारिज कर दिया। अधिनियम की धारा 34 के तहत एक चुनौती में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की व्याख्या स्पष्ट रूप से एक संभावित दृष्टिकोण था, जो दृष्टिकोण में उचित और निष्पक्ष था।

17. पुरस्कार के प्रासंगिक भाग को निकालना महत्वपूर्ण है, जहां न्यायाधिकरण ने विवाद III और IV से संबंधित संविदात्मक खंडों पर विचार किया और उनकी व्याख्या की:

“40. अनुबंध के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि दावेदार उसके द्वारा भुगतान किए गए प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। खंड 5.1।2 विशेष शर्तों में यह प्रावधान है कि कार्य अनुबंध पर बिक्री कर या कारोबार कर या कार्य के निष्पादन के दौरान प्रत्यर्थी को बिल की गई राशि पर लगाया गया या बढ़ाया गया अन्य कर प्रत्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि बेचे गए माल की कीमत रु। 2000/- और अनुबंध के समय, माल बिक्री कर के अधीन नहीं था, लेकिन बाद में काम के निष्पादन के दौरान, राज्य ने माल की ऐसी बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से बिक्री कर लगाया।

ठेकेदार खंड 5.1 के तहत प्राप्त करने का हकदार होगा। 2, रुपये की कीमत पर 5 प्रतिशत पर बिक्री कर। 2000/-। इसी तरह, यदि कार्य अनुबंध कर को अनुबंध करने के समय प्रचलित 4.2 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाता है, तो ठेकेदार अंतर का दावा करके उच्च दर का हकदार होगा। अतः, कौन-सा खंड 5.1।2 प्रत्यर्थी पर उठाए गए बिलों पर ठेकेदार द्वारा "प्रभार्य" कर लगाया जाता है। यह करों में वृद्धि की प्रतिपूर्ति से संबंधित नहीं है जो अप्रत्यक्ष रूप से उद्धृत मूल्य या दर का एक घटक हो सकता है और जो केवल मूल्य भिन्नता खंड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऐसा स्पष्ट रूप से इसलिए है क्योंकि जब कोई ठेकेदार किसी काम की वस्तु के लिए दर उद्धृत करता है, तो इस तरह की दर में सामग्री लागत, श्रम लागत, ईंधन लागत, अधिभार और लाभ जैसे विभिन्न घटक होंगे। ठेकेदार उद्धृत मूल्य को बनाने वाले विभिन्न घटकों के विभाजन का संकेत नहीं देता है। जाहिर है कि इस प्रकार उद्धृत दरों में, यदि इसमें किसी सामग्री का उपयोग शामिल है, सामग्री की लागत और उस पर भुगतान किया गया कोई भी कर शामिल होगा; और यदि इसमें कुछ मशीनरी/उपकरण का उपयोग शामिल है, तो इसमें मशीनरी/उपकरण के संबंध में किराया शुल्क और उस पर कोई भी कर शामिल होगा। अनुबंध से यह स्पष्ट है कि दर के ऐसे घटकों के संबंध में, दावेदार मूल्य या करों में किसी भी वृद्धि की प्रतिपूर्ति की मांग करने का हकदार नहीं है और वह जो कुछ भी पाने का हकदार होगा, वह वृद्धि होगी जिसकी अनुमति मूल्य भिन्नता खंड के सूत्र के अनुसार दी गई है। मूल्य भिन्नता खंड केवल एक मानकीकृत मूल्य भिन्नता सूत्र के अनुसार सामान्य तरीके से मूल्य भिन्नता प्रदान करता है, न कि वास्तविक वृद्धि की प्रतिपूर्ति। यही कारण है कि बी. ओ. क्यू. के खंड 11.7 में प्रावधान है कि दरों/कीमतों में सभी कर और खंड 7.1 शामिल होंगे। 1 7. 1.2 यह स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत और के. आर. सी. एल.

द्वारा स्वीकार की गई दरें, काम के पूरा होने तक अच्छी होंगी और मूल्य भिन्नता खंड के माध्यम से किए गए प्रावधान के अलावा कर या अन्य शुल्कों में वृद्धि के कारण कोई अतिरिक्त व्यक्तिगत दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

.....

43. जैसा कि ऊपर देखा गया है, अनुबंध में दावेदार द्वारा किए गए अप्रत्यक्ष लागत, करों की प्रतिपूर्ति पर विचार नहीं किया गया है।

कोंकण रेलवे कॉर्पो. लिमिटेड बनाम चीनब ब्रिज प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग [पामिदिगंतम श्री नरसिम्हा, जे.] 228 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

कार्य के निष्पादन के लिए अनुबंध में ठेकेदार को सभी परिस्थितियों और होने वाली सभी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किसी काम को निष्पादित करने के लिए एक कीमत का हवाला देने पर विचार किया जाता है। ठेकेदार को पता था कि वह केवल उद्धृत मूल्य और केवल मूल्य भिन्नता खंड द्वारा अनुमत मूल्य में परिवर्तन का हकदार है। अनुबंध में सामग्री या उस पर कर की कीमत में प्रत्येक वृद्धि के भुगतान या प्रतिपूर्ति का प्रावधान नहीं है, जो किसी कार्य के निष्पादन में जा सकता है।”

(जोर दिया गया) 18. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णयों पर रोक लगा दी। न्यायाधिकरण के निर्णय को बरकरार रखने का कारण यह नहीं है कि अधिनियम की धारा 34 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला एकल न्यायाधीश मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा संविदात्मक खंडों की व्याख्या से पूरी तरह सहमत है। अधिनियम की धारा 34 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले विद्वान न्यायाधीश ने इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा स्पष्ट किए गए मध्यस्थ पुरस्कार को चुनौती देने के दायरे को ध्यान में रखा। धारा 34 अधिकारिता का प्रयोग केवल इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि अनुबंध के तथ्यों और व्याख्या पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण मौजूद है। अपने शब्दों में, उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ का निष्कर्ष इस प्रकार है:

“10. ... अस्पष्टता खंड 5.1 से नहीं आती है। 1, लेकिन इस तथ्य से कि अनुबंध में अन्य खंड हैं, जैसे कि खंड 7.1।1 और 7.1।2. इन खंडों के सह-अस्तित्व को देखने का एक तरीका खंड 7.1 का इलाज करना है। 1 और 7.1।2 केवल मूल्य भिन्नता निर्धारित करने के लिए एक अपवर्जन के रूप में, क्योंकि यह खंड 5.1 में विशिष्ट रूप से प्रदान किया गया है। 2. समान रूप से, इन तीन खंडों को देखने का एक और तरीका है, और वह है: खंड 7.1।1 और 7.1।2 यह स्पष्ट करें कि बी. ओ. क्यू. दरों का हिस्सा बनने वाले किसी भी घटक के मामले में कर में कोई वृद्धि, जिस पर ठेकेदार द्वारा किसी विशेष वस्तु के लिए अपनी दरों को उद्धृत करने के लिए विचार किया गया था, ठेकेदार को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; यह केवल तभी है जब वास्तव में ठेकेदार की डिलीवरी पर विशेष करों का भुगतान किया जाना था, इन्हें खंड 5.1 के तहत नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए शामिल किया जाएगा। 2. मध्यस्थ ने बाद के

दृष्टिकोण को अपनाया। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक अनुचित दृष्टिकोण है या एक ऐसा दृष्टिकोण है जो या तो असंभव है या जिसे किसी भी निष्पक्ष और विवेकपूर्ण व्यक्ति ने नहीं लिया होगा। इस विवाद पर पुरस्कार, इस प्रकार, किसी भी हस्तक्षेप के योग्य नहीं है

एसोसिएट बिल्डर्स (उपरोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा बताए गए कानून को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 34।”

19. अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एक अलग रुख अपनाया। इसने राय दी कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा खंडों का निर्माण एक संभावित दृष्टिकोण भी नहीं था, और निम्नलिखित रूप में देखा गया:

“30. जो अधिक उपयुक्त है वह यह है कि यदि किसी अनुबंध के दो निर्माण संभव हैं, तो जो सभी खंडों को प्रभावी और आवाज देता है, उसे दूसरे पर प्राथमिकता दी जाएगी जो उनमें से एक को अनुचित या निरर्थक बनाता है [राधा सुंदर दत्ता बनाम मोहम्मद जहांदुर रहीम और अन्य, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 24]। यह सुझाव देने के लिए कुछ कानून है कि यदि कोई पुरस्कार समग्र रूप से अनुबंध का अर्थ नहीं है तो यह एक संभावित दृष्टिकोण नहीं है और यह विकृत है [साउथ ईस्ट एशिया मरीन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड बनाम ऑयल इंडिया लिमिटेड, (2020) 5 एससीसी 164; पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2020) 7 एससीसी 167]। जहां तक जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से लागू किए गए टोल कर के कारण प्रतिपूर्ति के विवाद का संबंध है, चिनाब पुल का मामला और भी मजबूत स्थिति में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टोल कर का खंड 5.1 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।² और मध्यस्थ दृष्टिकोण उन दो शब्दों को पूरी तरह से हटाने के बराबर है। यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है।”

20. उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अपनाए गए अनुबंधों की व्याख्या का सिद्धांत कि जब दो निर्माण होते हैं

संभव है, तो अदालतों को उसे पसंद करना चाहिए जो प्रभाव और आवाज देता है

सभी खंडों का पूर्ण अनुप्रयोग नहीं होता है। उक्त व्याख्या उस अधिकार क्षेत्र के अधीन है जिसका प्रयोग करने के लिए न्यायालय को कहा जाता है। अधिनियम की धारा 37 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, न्यायालय उस अधिकार क्षेत्र के बारे में चिंतित है जिसका प्रयोग न्यायालय ने मध्यस्थ पुरस्कार को चुनौती देने पर विचार करते समय किया था। अधिनियम की धारा 34 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण विकृत है या स्पष्ट रूप से मनमाना है। तदनुसार, एक वैकल्पिक दृष्टिकोण पर अनुबंध की पुनः व्याख्या करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यदि अधिनियम की धारा 34 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए यह सिद्धांत लागू होता है, तो 229 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाली एक खंड पीठ

अधिनियम की धारा 37 एक एकल न्यायाधीश के निर्णय को इस आधार पर उलट नहीं सकती है कि उन्होंने अनुबंध के सभी खंडों को प्रभाव और आवाज नहीं दी है। यही वह जगह है जहाँ उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अधिनियम की धारा 37 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक संविदात्मक खंड की पुनः व्याख्या करने में त्रुटि की। किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए राधा सुंदर दत्ता (उपरोक्त) में निर्णय 1959 में लिया गया था, और यह ग्राम चौकीदारी अधिनियम, 1870 और 1819 के बंगाल पटनी तालुक विनियमन के तहत उत्पन्न होने वाली कार्यवाही से संबंधित है। विशेष रूप से अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण और एकल न्यायाधीश द्वारा संविदात्मक खंड की समवर्ती व्याख्याओं में हस्तक्षेप करने के लिए इस निर्णय पर भरोसा करना उचित नहीं है।

21. जहां तक दक्षिण पूर्व एशिया मरीन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड (उपरोक्त) और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम नॉर्थ ईस्टर्न में निर्णयों का संबंध है।

इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 11 संबंधित है, दोनों मामलों में, इस न्यायालय ने अच्छे और वैध कारणों से अधिनियम की धारा 37 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय द्वारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ-साथ अधिनियम की धारा 34 के तहत अदालत के समवर्ती निर्णयों के साथ हस्तक्षेप को खारिज कर दिया। दक्षिण पूर्व में

एशिया मरीन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड (ऊपर), धारा 37

न्यायालय ने निर्णय में हस्तक्षेप किया क्योंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एच. एस. डी. की कीमत बढ़ाने वाले परिपत्र को "कानून का बल" समझते हुए "कानून में परिवर्तन" खंड के तहत उच्च गति वाले डीजल के लिए मूल्य वृद्धि के दावे की अनुमति दी। "कानून में परिवर्तन" खंड में "किसी भी कानून में परिवर्तन या अधिनियमन या मौजूदा कानून की व्याख्या" के कारण किसी भी अतिरिक्त लागत की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 37 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए और इस न्यायालय ने पाया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 'कानून में परिवर्तन' खंड को गलत तरीके से बल आकस्मिक खंड के समान समझा और दावों की अनुमति दी। इसे अनुबंध की संभावित व्याख्या नहीं माना गया और इसलिए, पुरस्कार को अलग कर दिया गया। इसी तरह, पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (उपरोक्त) में, मध्यस्थ पुरस्कार को अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित पाया गया और इसके परिणाम को अन्यायपूर्ण संवर्धन में पाया गया, जो अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत भारत की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन था। इसलिए, इन दोनों मामलों में, यह न्यायालय आश्वस्त था कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण भी नहीं था, और इसलिए, विकृत प्रकृति का था।

22. वर्तमान मामले में, हमने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा साक्ष्य की सराहना की है। हम.

11 (2020) 7 एससीसी 167।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

आश्चर्य है कि अनुबंध के तथ्यों और व्याख्या की उनकी सराहना उचित है, और इसमें एक संभावित दृष्टिकोण शामिल है। अधिनियम 1996 की धारा 5 के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, हम अवलोकन पर ध्यान देते हैं

विद्या द्रोलिया और ओ. आर. एस. बनाम में इस न्यायालय का। दुर्गा व्यापार निगम
13: “मध्यस्थता एक निजी विवाद समाधान तंत्र है जिसके तहत दो या दो से अधिक पक्ष अदालतों या कानून द्वारा साबित सार्वजनिक मंच द्वारा निर्णय के विकल्प के रूप में एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अपने वर्तमान या भविष्य के विवादों को हल करने के लिए सहमत होते हैं। पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवादों का न्यायालयों/सार्वजनिक मंच पर निर्णय लेने के अपने कानूनी अधिकार को छोड़ देते हैं। मध्यस्थता समझौता मध्यस्थ न्यायाधिकरण को विवादों पर निर्णय लेने और पक्षों को बांधने का संविदात्मक अधिकार देता है।”

23. उच्च न्यायालय की खंड पीठ का यह निष्कर्ष कि पुरस्कार विकृति के आधार पर अलग किए जाने योग्य है, गलत है, क्योंकि यह एसोसिएट बिल्डर्स बनाम दिल्ली में निर्धारित सिद्धांत की अनदेखी करता है।

विकास प्राधिकरण, 14 जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: “32. विकृति की एक अच्छी कार्यशील परीक्षा दो निर्णयों में निहित है। आवकारी और कराधान कार्यालय-सह-निर्धारण प्राधिकरण बनाम गोपी नाथ एंड संस [1992 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 312] में यह अभिनिर्धारित किया गया था: (एस. सी. सी. पी. 317, पैरा 7)

“7. ... इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी करके या उसे बाहर करके या अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए तथ्य का कोई निष्कर्ष निकाला जाता है या यदि तर्क की इतनी अपमानजनक रूप से अवहेलना की जाती है कि तर्कहीनता के दोष को विकृत होने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो तथ्य को कानून में असंवैधानिक माना जाता है।” कुलदिप सिंह बनाम कम्पापुलिस का [(1999) 2 एस. सी. सी. 10:1999 एससीसी (एल एंड एस) 429], यह आयोजित किया गया था: (एस. सी. सी. पी. 14, पैरा 10)

“10. इसलिए, उन निर्णयों के बीच एक व्यापक अंतर बनाए रखा जाना चाहिए जो विकृत हैं और जो

12 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, धारा 5: “5. न्यायिक हस्तक्षेप का विस्तार।—तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस भाग द्वारा शासित मामलों में, कोई भी न्यायिक प्राधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिवाय इसके कि इस भाग में ऐसा उपबंध किया गया हो।”

13 (2021) 2 एससीसी 1, पैरा 18।

14 (2015) 3 एस. सी. सी 49.

231

कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम चिनाब ब्रिज परियोजना का प्रबंधन [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.]

नहीं हैं। यदि कोई निर्णय बिना किसी साक्ष्य या साक्ष्य के लिया जाता है जो पूरी तरह से अविश्वसनीय है और कोई भी उचित व्यक्ति उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो आदेश विकृत होगा। लेकिन अगर अभिलेख पर कुछ सबूत हैं जो स्वीकार्य हैं और जिन पर भरोसा किया जा सकता है, तो यह कितना भी व्यापक क्यों न हो, निष्कर्षों को विकृत नहीं माना जाएगा और तथ्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

33. यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि जब कोई अदालत मध्यस्थता पुरस्कार के लिए "सार्वजनिक नीति" परीक्षण लागू कर रही है, तो यह अपील की अदालत के रूप में कार्य नहीं करती है और इसके परिणामस्वरूप तथ्य की त्रुटियों को ठीक नहीं किया जा सकता है। तथ्यों पर मध्यस्थ द्वारा एक संभावित दृष्टिकोण को अनिवार्य रूप से पारित करना पड़ता है क्योंकि मध्यस्थ साक्ष्य की मात्रा और गुणवत्ता का अंतिम स्वामी होता है जिस पर वह अपना मध्यस्थ निर्णय देता है। इस प्रकार कम साक्ष्य या साक्ष्य के आधार पर एक पुरस्कार जो एक प्रशिक्षित कानूनी दिमाग के लिए गुणवत्ता में माप नहीं करता है, इस स्कोर पर अमान्य नहीं माना जाएगा।”

(जोर दिया गया) 24। मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समवर्ती निर्णयों को दरकिनार करने में त्रुटि की है। अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय को विकृत या स्पष्ट रूप से अवैध नहीं कहा जा सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निष्कर्ष निकाला है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है, और एकल न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 34 के तहत इसमें हस्तक्षेप करने से परहेज किया। हमारी राय है कि खंड पीठ को इन आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

25. ऊपर बताए गए कारणों से, हम 2023 की सिविल अपील संख्या 2903 की अनुमति देते हैं और 2019 की अपील संख्या 458 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के

फैसले को दरकिनार करते हैं और 2015 की मध्यस्थता याचिका संख्या 546 में एकल न्यायाधीश के फैसले और आदेश को पुनर्स्थापित करते हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन